IGSD
Launch of the Report on
Tackling Non-CO_2 Emissions: Pathways for Himachal Pradesh
by

IGSD
Launch of the Report on
by
Thakur Sukhvinder Singh Sukhu

हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में इस वर्ष 200 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाएंगे : सुक्खू

गैर-कार्बन उत्सर्जन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करने के मौके पर बोले सीएम

- औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से दो एमओए हस्ताक्षरित
- नालागढ़ में एक मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा

गैर.कार्बन उत्सर्जन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करते मुख्यमंत्री व अन्य।

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 24 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और सिकुड़ते ग्लेशियरों को जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि समय रहते ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाना अनिवार्य है। उन्होंने साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाईऑक्साइड एमीशंस पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश शीर्षक रिपोर्ट जारी करते हुए राज्य की जलवायु रणनीति को और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। शिमला में राज्य पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अप्रत्याशित बादल फटना, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों का तेजी से सिकुड़ना गंभीर चेतावनी हैं। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उस दौरान 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा है और यहां की पारिस्थितिकी में अस्थिरता का असर पूरे देश पर पड़ेगा।

इस अवसर पर औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो समझौता ज्ञापनों (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता डाबर इंडिया के साथ हुआ, जिसके तहत कंपनी प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराएगी और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधों का वितरण करेगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियां दी जाएंगी। जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला, पदम काष्ठ और पुष्करमूल के पौधे वितरित होंगे। अल्पाइन क्षेत्रों के किसानों को अतीस और विष जैसी दुर्लभ जड़ी-बूटियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

दूसरा एमओए सोलन के मैसर्स करण सिंह वैद्य के साथ पांच वर्षों के लिए किया गया है। इसके तहत हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी, तलसी, चिरायता और हिमालयन जेंटियन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वर्ष 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी और 38 हजार टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हिमाचल अपने वैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करेगा और लंबित मुद्दों के समाधान के बाद ही आगामी जलविद्युत परियोजनाओं पर आगे बढ़ेगा।इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा , सचिव (पर्यावरण ,विज्ञान , प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एसके सिंगला , यूएनडीपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डॉ डर्बुड जैल्के , मार्टिना ओटो , डायरेक्टर इंडिया ग्रेग्राव आईजीएसडी जेरिन ओशोए निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

नॉन-सीओ2 उत्सर्जन से निपटने के लिए सरकार औषधीय पौधों की खेती व संरक्षण पर देगी जोर

मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में दो एमओयू साइन, डाबर इंडिया हर साल उपलब्ध कराएगी 12 लाख पौधे

शिमला| नॉन-सीओ2 उत्सर्जन से निपटने के लिए सरकार औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण पर जोर देगी। इसके लिए औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में दो एमओयू साइन किए गए। एक समझौता डाबर इंडिया और दूसरा सोलन की फर्म कर्ण सिंह वैद्य के साथ हुआ। डाबर इंडिया अगले दस वर्षों तक हर साल 12 लाख पौधे किसानों को फ्री देगी। निचले और मध्यम पहाड़ी इलाकों में आंवला, हरड़, बहेड़ा और लोधरा जैसे पौधे दिए जाएंगे, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला और पुष्करमूल जैसी जड़ी-बूटियां उगाई जाएंगी। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अतीस और विष जैसी अल्पाइन प्रजातियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यहीं नहीं किसानों से जड़ी बूटियां भी डाबर खरीदेगा।

सोलन जिले में किए गए दूसरे समझौते के तहत हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, चिरायता और हिमालयन जेंटियन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआत में 225 महिला किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताई चिंता

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदेश में बढ़ते बादल फटने की घटनाओं और अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और तेजी से सिकुड़ते ग्लेशियर पर चिंता जताई। उन्होंने इन हालात को गंभीर चेतावनी बताते हुए समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस साल 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नालागढ़ में आएक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में 300 नई ई-बसें शामिल होंगी और 38 हजार टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। • शेष पेज 9 पर

बादल फटना व सिकुड़ते ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत

सीएम ने जारी की साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन-डाईऑक्साइड एमीशनस रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो प्रमुख ■ शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाईऑक्साइड एमीशनस : पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और 10 वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएंगे। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियां) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत 6 प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है की खेती की जाएगी। इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

● राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमओए हस्ताक्षरित

प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भू स्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

हिमाचल केवल एक भू-भाग नहीं, हिमालय की आत्मा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक भू-भाग ही नहीं है, बल्कि हिमालय की आत्मा है। ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत इसकी पहचान हैं और इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के दुष्परिणाम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाए के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

अप्रत्याशित बादल फटने की घटनाएं जलवायु परिवर्तन की संकेतः सुक्खू

राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एमओए हस्ताक्षरित

टीना ठाकुर

शिमला (जगमार्ग न्यूज)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज 'साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बनडाईऑक्साइड एमीशनसः पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएंगे। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियाँ) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा, सचिव (पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एस.के. सिंगला, यूएनईपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डॉ. डर्वुड जैल्के, मार्टिना ओटो, डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम आईजीएसडी जेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

छह प्राथमिकता वाली प्रजातियों की होगी खेती

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है की खेती की जाएगी। इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

सरकार औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को करेगी प्रोत्साहित : सुक्खू

डाबर इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ किए एम.ओ.ए.; 10 वर्षों में 1.20 करोड़ पौधे उपलब्ध करवाएगी डाबर, सोलन में 225 महिला किसान जुड़ेंगी

शिमला, 24 फरवरी (ब्यूरो): प्रदेश सरकार राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ दो मैमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। पहले एम.ओ.यू. के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म एक लाख) उपलब्ध करवाएगी। 10 वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे।

दूसरा एम.ओ.यू. मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ 5 वर्षों के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत सोलन जिले में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को जोड़ा जाएगा, साथ ही आसपास की पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा।

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में में गैर सीओटू उत्सर्जन से निपटने के वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए। (नरेश)

डाबर ने हिमालयी औषधीय पौधों की स्थायी खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ की साझेदारी

सचिन वर्मा/देवभूमि मिरर

शिमला, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए डाबर इंडिया लिमिटेड ने हिमालयी औषधीय पौधों की स्थायी खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू साईन किया है। इस साझेदारी में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड,वन विभाग और आयूष विभाग शामिल हैं। डाबर रीसर्च एंड डेवलपमेन्ट सेंटर में बायोरिसोर्सेज़ के हैड डॉ पंकज रतुरी तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के सदस्य सचिव आईएएस डी. सी. राना ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु भी मौजूद रहे।इस साझेदारी का उद्देश्य हिमालय के विशेष औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है खासतौर पर वे पौधे जिन्हें साइट्स के तहत सूचीबद्ध किया गया है जिनकी संख्या जंगलों में लगातार घट रही है।इन पौधों की खेती को बढ़ावा देकर यह पहल आने वाले समय में एक्सेस एंड बेनेफिट शेयरिंग लायबिलिटीज़ को कम करेगी तथा कच्चे माल की सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाएगी। डाबर इंडिया लिमिटेड में ग्लोबल ऑपरेशन्स हैड सौरभ लाल ने कहा,देश की अग्रणी विज्ञान पर आधारित आयुर्वेद कंपनी होने के नाते डाबर ने पृथ्वी की देखभाल,इसके सौंदर्य को बनाए रखने तथा भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमें गर्व है कि हम न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट में बल्कि एनवायरनमेन्ट सस्टेनेबिलिटी में भी नए इनोवेशन्स लाते रहते हैं। इसी सोच के साथ हम समुदायों के सहयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखने,बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को कम करने,दुर्लभ औषधीय पौधों को लुप्त होने से बचाने,दुर्लभ जड़ी.बूटियों की स्थायी खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखते हैं। हमारा यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है जो समुदायों को आत्मनिर्भरता के साथ अपने क्षेत्र में स्थायी बदलाव लाने में सक्षम बनाएगा।

यह साझेदारी हिमालय के विशेष एग्रो.क्लाइमेट ज़ोन में कम मात्रा में उगने वाली उच्च मूल्य की औषधीय फसलों पर फोकस करेगी। क्लस्टर.आधारित कल्टीवेशन मॉडल के ज़रिए यह प्रोग्राम खेती को बदलते मौसम के प्रभाव से सुरक्षित कर ग्रामीण किसानों को आय के स्रोत प्रदान करेगा। इस खेती से आयुर्वेदिक उद्योग को ऐसी उच्च गुणवत्ता की जड़ी.बूटियां आसानी से मिल सकेंगी।

किसानों को दस साल तक मुफ्त में बांटे जाएंगे एक करोड़ 20 लाख औषधीय पौधे

हर वर्ष मिलेंगे 12 लाख पौधे, डाबर कंपनी के साथ करार

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। डाबर कंपनी हिमाचल प्रदेश के किसानों को 12 लाख औषधीय पौधे हर साल देगी। इनमें अलग-अलग प्रजाति के एक-एक लाख पौधे होंगे। यह पौधे आगामी दस साल तक दिए जाते रहेंगे।

सरकार ने डाबर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। इसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर्ज डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्ज करण सिंह वैद्य सोलन के साथ साइन किया गया।

हर प्रजाति के 1-1 लाख पौधे दिए जाएंगे

मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुए इस समझौते के अनुसार मैसर्ज डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश को दस साल में कुल एक करोड़ 20 लाख पौधे देगा। यह पौधे 10 साल तक कम से कम 10 लाख प्रति प्रजाति दिए जाएंगे। इन्हें किसानों को मुफ्त दिया जाएगा। इन पौधों को प्रदेश के पारिस्थितिकीय संतुलन को देखते हुए चयनित किया जाएगा। इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट के विमोचन कार्यक्रम में बोलते सीएम। स्रोत : विभाग

किसानों को इस तरह मिलेंगे मुफ्त पौधे

निम्न और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला में आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोध्रा जैसी प्रजातियों का वितरण किया जाएगा। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में जटामांसी, कुटकी, सुगंधवाला (जड़ी-बूटी), पदुम कष्ट (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी-बूटी) जैसी प्रजातियों का वितरण किया जाएगा। किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों के उच्च क्षेत्रों में किसानों को अतीश और विष (जड़ी-बूटी) जैसी अल्पाइन प्रजातियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

हल्दी, अश्वगंधा, तुलसी के पौधे सोलन में उगाने का अलग समझौता : सोलन स्थित मैसर्स करण सिंह वैद्य के साथ हस्ताक्षरित दूसरे समझौता ज्ञापन (एमओए) के तहत पांच वर्षों की अवधि के लिए सोलन जिले में चुनिंदा औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इस समझौते के अंतर्गत छह प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों - हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, चिरायता और हिमालयन जेंटियन की खेती आसपास की पंचायतों को लक्षित करते हुए की जाएगी। प्रारंभिक चरण में, 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

अप्रैल तक 300 नई ई बसें खरीदेंगे : सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी।

विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। 38,000 टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसे आगे बढ़ाना होगा। राज्य में 2032 तक समृद्धशाली राज्य बनाने की तैयारी है। ब्यूरो

ठोस आश्वासन नहीं मिला तो किशाऊ और रेणुका बांध जैसी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा।

16वें वित्तायोग ने आरडीजी के लिए न तो हां की न मना : मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्तायोग ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के लिए न तो हां की और न ही न किया है। आरडीजी के बारे में मंत्रिमंडल ने हाईकमान के सामने विचार रखे कि प्रदेश के साथ बहुत न्याय हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री से बात करनी थी, मगर वह सोमवार को बेंगलूरु गई हैं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल भवन में बगैर वारंट के रेड होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अप्रत्याशित बादल फटने की घटनाएं और सिकुड़ते ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के संकेतः मुख्यमंत्री

प्रचण्ड समय . शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज 'साईंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैक्लिंग नॉन कार्बनडाईऑक्साइड एमीशनस: पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधवाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ट (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएंगे। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियां) किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसस), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टीया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है की खेती की जाएगी। इसमें आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और युवाओं को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

प्रचण्ड समय

नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी। विभिन्न सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 38,000 टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक भू-भाग ही नहीं है बल्कि हिमालय की आत्मा है। ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत इसकी पहचान हैं और इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के दुष्परिणाम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा, सचिव (पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एस.के. सिंगला, यूएनडीपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डॉ. डबुंड जैल्के, मार्टिना ओटो, डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम आईजीएसडी जेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक पहल

सीएम ने जारी की वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट औषधीय पौधों की खेती को दिया बढ़ावा

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'साईंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाईऑक्साइड एमीशन्स पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अचानक बादल फटना, बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर सिकुड़ना जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। वर्ष 2023 की आपदा में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे, जो चेतावनी हैं।

औषधीय पौधों की संगठित खेती के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड और करण सिंह वैद्य के साथ समझौते किए गए। डाबर ईंडिया प्रतिवर्ष 12 लाख पौधे प्रदान करेगी। निम्न और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में आंवला, हरड़, बहेड़ा जैसी प्रजातियां, उच्च व अल्पाइन क्षेत्रों में जटामांसी, कुटकी जैसी जड़ी-बूटियां वितरित की जाएंगी। सोलन जिले में 108 बीघा भूमि पर हल्दी, अश्वगंधा और अन्य औषधीय पौधों की खेती में 225 महिला किसान शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने और 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प जताया।

नालागढ़ में हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा स्थापित

नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही अप्रैल तक एचआरटीसी के बेड़े में लगभग 300 नई ई-बसें शामिल की जाएंगी और 38 हजार टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के बकाये का उठा मुद्दा

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये का मुद्दा भी उठाया और स्पष्ट किया कि जब तक पड़ोसी राज्यों से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमालय की सुरक्षा और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही आपदाएं

सीएम सुक्खू शिमला में बोले, अप्रत्याशित बादल फटने की घटनाएं और सिकुड़ते ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के संकेत

शिमला – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 'साइंटिफिक असेस्मेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमीशंस: पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी करते हुए

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है। इससे राज्य में अप्रत्याशित बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को प्राकृतिक चेतावनी समझते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 'साइंटिफिक असेस्मेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमीशंस : पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य, सोलन के साथ राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) भी हस्ताक्षरित किए गए हैं।

पहले एमओए के तहत डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और दस वर्षों में कुल 1.20 करोड़ पौधे (प्रति प्रजाति 10 लाख) उनकी पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और शिमला के निचले क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला (जड़ी-बूटियां), पदम काष्ठ (वृक्ष) और पुष्करमूल (जड़ी) के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएंगे। अल्पाइन प्रजातियां जैसे अतीस और विष (जड़ी-बूटियां) किन्नौर, लाहुल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनारथा, एसके सिंगला, यूएनईपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डा. डर्वुड जैल्के, मार्टिना ओटो, डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम आईजीएसडी जेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

दूसरा समझौता पांच साल के लिए

दूसरा एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन में औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां जिनमें हल्दी (कुर्कुमा लोंगा), अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफेरा), शतावरी (एस्पैरागस रेसमोसम), तुलसी (ओसिमम सैंक्टम), चिरायता (स्वर्टिया चिरायिता) और हिमालयन जेंटियन (जेंटियाना कुरू) शामिल है, की खेती की जाएगी। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

हिमालय में अस्थिरता के दुष्परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक भू-भाग ही नहीं है, बल्कि हिमालय की आत्मा है। ग्लेशियर, नदियां, वन और पर्वत इनकी पहचान हैं और इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के प्रभाव न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश पर पड़ेंगे। राज्य अपने वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाया के निपटारे के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

राज्यसभा के लिए हाइकमान तय करेगा प्रत्याशी

मुख्यमंत्री बोले, राहुल गांधी और खड़गे लेंगे आखिरी फैसला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अभी समय है। राज्यसभा के चुनाव का फैसला हाईकमान करती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी का चयन करेंगे। हाईकमान की इसका निर्णय लेगा। इसके बाद हम उन्हें वोट डालकर उसे राज्यसभा भेजेंगे। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग करे, लेकिन वे सहयोग करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्तायोग के पास भाजपा और जयराम ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष गए और कहा कि हमें आरडीजी मिलनी चाहिए, लेकिन विधानसभा में हिमाचल के हितों और अधिकारों की रक्षा के हितों की बात आई, तो वह हल्ला करते रहे। ऐसे में प्रदेश का हित कैसे होगा। कौन प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रहा है, यह सब जनता देख रही है।

सुक्खू ने कहा, हिमाचल सदन पर रेड दुर्भाग्यपूर्ण

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि दिल्ली के हिमाचल सदन में हुई रेड दुर्भाग्यपूर्ण है। वह वहां ठहरे हुए थे। हमारे यूथ कांग्रेस के युवा वहां आते हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे थे कि सीएम कार्यालय से वहां की बुकिंग होती है। सुक्खू ने कहा कि सीएम कार्यालय से बुकिंग नहीं होगी, तो कहां से होगी? हम उनकी बुकिंग नहीं, सबकी बुकिंग करते हैं। हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। उसका वह किराया देते हैं। यदि वे ठहरे थे और इस प्रकार की यदि रेड करनी थी, तो उसकी जानकारी आरसी को देनी चाहिए थी। उन्हें भी जानकारी नहीं दी। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। लोकतंत्र में जो शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता है, तो उसे विरोध नहीं कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिए गए।

सुक्खू बोले, बादल फटना व सिकुड़ते ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के संकेत

- नान कार्बन-डाईआक्साइड एमीशंस से निपटने के वैज्ञानिक आकलन पर रिपोर्ट जारी
- हिमाचल में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र हस्ताक्षरित

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 'साइंटिफिक असेसमेंट आफ टैकलिंग नान कार्बनडाई आक्साइड एमीशंसः पाथवेज फार हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपार्ट जारी करने से जुड़े कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए ● सौजन्य डीपीआरओ

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन गंभीर वैश्विक समस्या है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने जैसी आपदा देखने को मिल रही हैं। उन्होंने इसे प्राकृतिक चेतावनी मानते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्ष 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में 23,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में 'साइंटिफिक असेसमेंट आफ टैकलिंग नान कार्बनडाईआक्साइड एमीशंसः पाथवेज फार हिमाचल प्रदेश' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई पहल की गई हैं। तीन वर्ष पहले सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर, मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र भी हस्ताक्षरित किए। डाबर इंडिया लिमिटेड किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख गुणवत्तापूर्ण पौधे (प्रति किस्म के एक लाख) और 10 वर्ष में 1.20 करोड़ पौधे पारिस्थितिकीय अनुकूलता के अनुसार उपलब्ध करवाएगी। निम्न एवं मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, काकड़ासिंगी और लोधर जैसी प्रजातियों के पौधे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जिलों और निचले शिमला क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। मध्य से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जटामांसी, कुटकी, सुगंधबाला, पदम काष्ठ और पुष्करमूल के पौधे कुल्लू, चंबा, मंडी, ऊपरी शिमला और किन्नौर जिलों में वितरित किए जाएंगे।

मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन पांच वर्ष की अवधि के लिए सोलन जिले में चयनित औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और मूल्य शृंखला विकास को बढ़ावा देगा। समझौते के तहत छह प्राथमिकता वाली प्रजातियां (हल्दी, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, चिरायता और हिमालयन जेंटियन) की खेती की जाएगी। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार और हरीश जनार्था, सचिव (पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) एस.के. सिंगला, यूएनईपी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की सचिवालय प्रमुख डा. डर्वुड जैल्के, इंस्टीट्यूट फार गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आइजीएसडी) के इंडिया प्रोग्राम डायरेक्टर जेरिन ओशो, निदेशक डीसी राणा तथा अन्य उपस्थित थे।

संपादकीय » चिंता की बात

गैर-कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन से निपटेगा हिमाचल >> पेज-4